



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 4, 2007/ज्येष्ठ 14, 1929

No. 145]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 4, 2007/JYAISTHA 14, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2007

विषय : चीन से डायक्लोफेनैक सोडियम के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 14/4/2007-डीजीएडी.- जबकि मै0 कैरव केमिकल्स लि0 मै0 अमोली ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एवं मै0 आरती ड्रग्स लि0 ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण एवं क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात पाटनरोधी नियम कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष याचिका दायर की है जिसमें चीन (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डायक्लोफेनैक सोडियम (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की पाटनरोधी जांच करने और इस प्रकार की पाटित संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

और प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंधी की मौजूदगी के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं और इसलिए प्राधिकारी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, एतद्वारा उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

2. विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद 'डायक्लोफेनैक सोडियम' (जिसे एतदपश्चात डीएफएस भी कहा गया है) है जिसे 2- [(2,6-डायक्लोरोफेनाइल), अमीनो] बेन्जीन एसिटिक एसिड मोनो

सोडियम साल्ट; [(2,6-डायक्लोरोएनीलिनों) फेनाइल एसिटिक एसिड सोडियम साल्ट] के रूप में भी जाना जाता है। डायक्लोफेनैक सोडियम सफेद अथवा हल्का पीला दानेदार पाउडर कुछ आर्द्रताग्राही प्रकृति का तथा पानी में कम घुलनशील होता है। डीएफएस के दो ग्रेड होते हैं - टैबलेट तथा इंजेक्टेबल ग्रेड। दोनों ग्रेडों में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। डायक्लोफेनैक सोडियम का उपयोग प्रमुखतः दाहरोधी एवं दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है।

डायक्लोफेनैक सोडियम एक कार्बनिक रसायन है जिसे सामान्यतः सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत किया जाता है। डीएफएस को 29420090 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

3. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

भारत में संबद्ध वस्तुओं के चार उत्पादक हैं अर्थात् कैरव केमिकल्स लि०, अमोली ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, आरती ड्रग्स लि० एवं मेडिटेक केमिकल्स लि०। यह याचिका कैरव केमिकल्स लि०, अमोली ऑर्गेनिक्स लि० तथा आरती ड्रग्स लि० द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई है। मेडिटेक केमिकल्स लि० ने याचिका का समर्थन किया है। इसके अलावा याचिकाकर्ता कम्पनियों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में एक प्रमुख हिस्सा है। याचिका, नियमों के तहत मानदण्डों को पूरा करती है और नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग हैं। पाटनरोधी नियमों के नियम 2(ख) एवं नियम 5(3)(क) के अनुसार याचिकाकर्ता को घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार है।

4. समान वस्तु

याचिकाकर्ताओं का यह दावा है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डायक्लोफेनैक सोडियम और संबद्ध देशों से निर्यातित डायक्लोफेनैक सोडियम के बीच कोई खास अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डायक्लोफेनैक सोडियम और संबद्ध देश से आयातित डाइक्लोफेनैक सोडियम के बीच भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, संबद्ध कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और इनमें काफी मिलती-जुलती विशेषताएं हैं। आगे यह दावा किया गया है कि उपभोक्ता इन दोनों का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित डायक्लोफेनैक सोडियम को पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित डायक्लोफेनैक सोडियम के समान उत्पाद माना जा रहा है।

5. शामिल देश

वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जनवादी गणराज्य है (जिसे चीन अथवा संबद्ध देश भी कहा गया है)।

6. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है। अतः याचिकाकर्ताओं ने परिकलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा किया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देशों की कीमतों अथवा लागतों के आधार पर नहीं किया जा सकता क्योंकि अनेक देशों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है और

इस संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने भारत में विधिवत ढंग से समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।

7. निर्यात कीमत

निर्यात कीमत का निर्धारण इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उत्पाद किसी विशिष्ट वर्गीकरण के तहत नहीं आता है, आईबीआईएस द्वारा संकलित सौदेवार आंकड़ों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत का निर्धारण भी सीआईएफ कीमत तथा कारखाना-द्वार निर्यात कीमत का निर्धारण करने हेतु भाड़े, ऋण लागत, बैंक प्रभारों, अंतर्देशीय भाड़ा, बीमा और कमीशन इत्यादि के लिए कीमत समायोजनों के विभिन्न तत्वों को अपनाते हुए किया गया है।

8. पाटन मार्जिन

इस बात के पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से काफी अधिक हैं जिससे प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ता ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप निरपेक्ष रूप से आयातों में वृद्धि तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में वृद्धि, अत्यधिक कीमत कटौती, चीन के बाजार हिस्से में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट, लाभ में कमी, लगाई गई पूंजी पर आय, वर्ष 2005-06 तक नकद लाभ में सुधार प्रदर्शित होने के पश्चात गिरावट इत्यादि के संदर्भ में हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। यह भी नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जा रहा था। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य है कि याचिकाकर्ताओं को संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति उठानी पड़ रही है। इसके अलावा, वास्तविक क्षति के अतिरिक्त याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि आयातों में वृद्धि की दर, उल्लेखनीय कीमत कटौती तथा उल्लेखनीय अप्रयुक्त क्षमताओं पर आधारित पाटित आयातों से वास्तविक क्षति का खतरा हो रहा है।

10. जांच अवधि (पीओआई) :

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच अवधि (पीओआई) जनवरी-दिसम्बर, 2006 है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 2003 - मार्च, 2004; अप्रैल 2004 - मार्च, 2005; अप्रैल, 2005- मार्च, 2006 तथा जांच अवधि शामिल होगी।

11 सूचना प्रस्तुत करना

सम्बद्ध देश के निर्यातकों, भारत स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में सम्बन्धित समझे जाने वाले आयातकों और नियोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग से निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। इस जांच में भागीदारी करने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित पते पर लिख सकता है:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय,
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग,
कमरा सं० 240, उद्योग भवन,
नई दिल्ली - 110011

कोई अन्य हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकती है।

12. समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए जो इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस (40) दिनों से पूर्व उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच जाए। तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है उन्हें उक्त सूचना, उन्हें लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

13. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

निर्यमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों द्वारा प्राधिकारी को प्रदत्त किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्ष की राय में यदि सूचना का संक्षिप्तिकरण सम्भव नहीं है, तो उसके कारणों का विवरण प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

14. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्ष उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है। जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश रखे गए हैं।

यदि कोई हितबद्ध पक्ष आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है, अथवा उचित समय के भीतर इसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2007

Sub :—Initiation of Anti-Dumping investigation concerning the imports of Diclofenac Sodium from China

F. No. 14/4/2007-DGAD.—Whereas M/s. Kairav Chemicals Limited, M/s. Amoli Organics Limited & M/s. Aarti Drugs Limited have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as AD Rules), alleging dumping of Diclofenac Sodium (hereinafter referred to as the subject goods), originating in or exported from China (hereinafter referred to as the subject country) and have therefore requested for initiation of an anti-dumping investigation against the imports of the subject goods from the subject country and levy anti-dumping duty on the such dumped subject goods.

AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rule 5 of the said Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

2. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present petition is "Diclofenac Sodium", (also referred as DFS hereinafter) also described as 2-[(2,6-Dichlorophenyl), Amino] Benzene Acetic Acid Mono Sodium Salt; [O-(2,6- Dichloroanilino) Phenyl Acetic Acid Sodium Salt. Diclofenac Sodium is white or slightly yellowish crystalline powder, slightly hygroscopic in nature and sparingly soluble in water. DFS has two grades-tablet and injectable grade. There is no significant difference in two grade. Diclofenac Sodium is primarily used as anti inflammatory and analgesic drug.

Diclofenac Sodium is an organic chemical normally classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act. DFS is classified under 29420090. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

3. DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

There are four producers of subject goods in India, namely Kairav Chemicals Limited, Amoli Organics Limited, Aarti Drugs Limited and Meditech Chemicals Ltd. The petition has been jointly filed by Kairav Chemicals Limited, Amoli

2654 GT/07-2

Organics Limited and Aarti Drugs Limited. Meditech Chemicals Ltd. has supported the petition. Further, the production by petitioner companies constitutes a major proportion in the Indian production. The petition satisfies the condition of standing under the Rules and the petitioners constitute "domestic industry" within the meaning of the Rules. The applicants have the standing to file the present petition for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

4. LIKE ARTICLE

Petitioners have claimed that there is no significant difference in Diclofenac Sodium produced by the domestic industry and Diclofenac Sodium exported from the subject country. Diclofenac Sodium produced by the domestic industry is comparable to Diclofenac Sodium imported from subject country in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Both the products are technically and commercially substitutable and hold closely resembling characteristics. It is further claimed that the consumers have used the two interchangeably. For the purpose of present investigation, Diclofenac Sodium produced by the petitioners is being treated as like article to Diclofenac Sodium imported from the subject country within the meaning of the Anti Dumping Rules.

5. COUNTRIES INVOLVED

The country involved in the present investigations is the People's Republic of China (also referred to as China or subject country).

6. NORMAL VALUE

The petitioners have claimed that China is a non-market economy. The petitioners have therefore, claimed determination of normal value on the basis of constructed cost of production. Petitioners have claimed that normal value cannot be determined on the basis of price or costs in third countries for the reason that the goods are not produced in several countries and no information is publicly available in this regard. Petitioners have determined normal value on the basis of cost of production in India, duly adjusted.

7. EXPORT PRICE

The export price has been determined based on the transaction wise data compiled by IBIS, considering that the product does not have dedicated classification. Net export price has also been determined from the CIF price and adopting various elements of price adjustments towards freight, credit cost, bank charges, inland freight, insurance and commission etc to arrive at ex-works export price.

8. DUMPING MARGIN

There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export price indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject country.

9. INJURY AND CAUSAL LINK

Petitioners have furnished evidence regarding injury having taken place as a result of the alleged dumping in terms of increase in imports in absolute terms and relative to production & consumption in India, significant price undercutting, increase in market share of China and decline in the market share of the domestic industry, deterioration in profits, return on capital employed, cash profits after improvements up to 2005-06, etc. It is also noted that the product was attracting anti dumping duties during the injury period. There is sufficient prima-facie evidence of material injury being suffered by the petitioners caused by dumped imports from subject countries. Further, in addition to material injury, petitioners have claimed that the imports are causing threat of material injury from the dumped imports based on rate of increase in imports, significant price undercutting and significant unutilized capacities.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI):

The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is January - December 2006. The injury investigation period will however, cover the period April, 2003-March, 04; April, 2004-March, 05; April, 2005-March, 06 and period of investigation.

11. SUBMISSION OF INFORMATION:

The exporters in the subject country and their Government through their embassy in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No. 240, Udyog Bhavan,
New Delhi-110011

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty (40) days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being addressed separately, are, however, required to submit the information within (40) forty days from the date of the letter addressed to them. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules *supra*.

13. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS

In terms of Rule 7, the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof, is required to be provided.

14. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6 (7), any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority